

## पश्चिमी घाट पारस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र

### प्रलिस के लयः

[पश्चिमी घाट](#), [पारस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र \(ESA\)](#), [गाडगलि समति](#), [पश्चिमी घाट पारस्थितिकी वशिषज्ज पैनल \(WGEEP\)](#), [कसतुरीरंगन समति](#)

### मेन्स के लयः

[पश्चिमी घाट का महत्त्व](#), [पश्चिमी घाट के समकष खतरे](#)

[स्रोत:इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [कर्नाटक](#), [महाराष्ट्र](#) और [गोवा](#) (उन छह राज्यों में से तीन, जहाँ केंद्र सरकार ने [पश्चिमी घाटों](#) के संरक्षण हेतु [पारस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों \(ESA\)](#) का प्रस्ताव दिया है) ने विकास परियोजनाओं को पूरा करने हेतु नरिधारित ESA क्षेत्रों को सीमति करने का अनुरोध किया है।

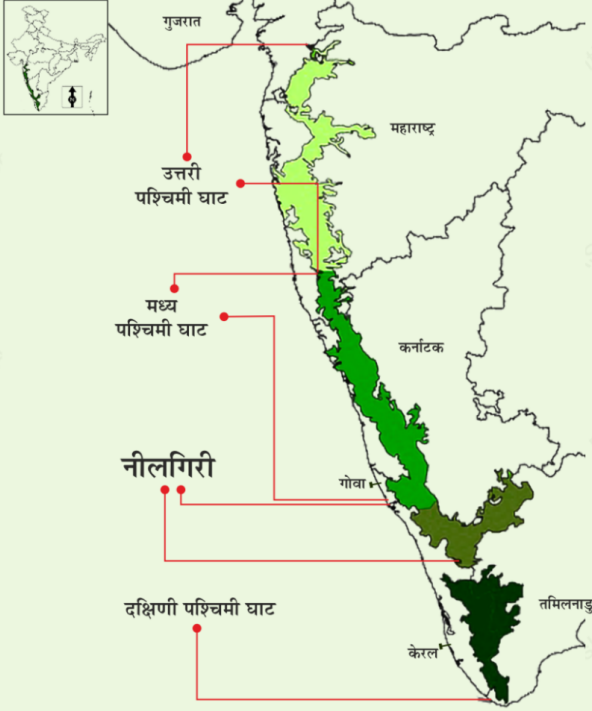
## पश्चिमी घाट पारस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र:

### परचिय:

- वर्ष 2013 में सरकार ने पश्चिमी घाट की जैवविधिता के संरक्षण हेतु सफारशें करने के लयिडॉ. [कसतुरीरंगन की अध्यक्षता](#) में एक [उच्च सतरीय कार्यसमूह](#) का गठन किया, जससे इस क्षेत्र के धारणीय एवं समावेशी विकास को बढ़ावा मलि सके।
  - इससे पहले [माधव गाडगलि समति \(2011\)](#) ने भी पश्चिमी घाट के संरक्षण के लयि अपनी सफारशें दी थी।
- इस समति ने सफारशि की थी किकेरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमलिनाडु में पहचाने गए प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को ESA घोषति किया जाए।
  - इस समति द्वारा पश्चिमी घाट के केवल **37% भाग** (जो गाडगलि समतिकी रपिर्ट में सुझाए गए 64% से काफी कम है) को ही ESA के तहत लाने की सफारशि की गई।

# पश्चिमी घाट

भारत के चार जैवविविधता हॉटस्पॉट में से एक; यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त (2012)



## नाम

- सह्याद्री- उत्तरी महाराष्ट्र; सह्य पर्वतम- केरल

## पर्वत प्रकार के बारे में विविध दृष्टिकोण

- दृष्टिकोण 1: अरब सागर में भूमि के एक हिस्से के नीचे की ओर मुड़ने के कारण बनने वाले भ्रंशोत्थ पर्वत
- दृष्टिकोण 2: वास्तव में पर्वत नहीं बल्कि दक्कन के पठार के भ्रंशोत्थ कगार/किनारे

## प्रमुख चट्टानें

- बेसाल्ट, ग्रेनाइट नीस, खोंडालाइट, कायांतरित नीस, क्रिस्टलीय चूना पत्थर, लौह अयस्क

## भौगोलिक विस्तार

- सतपुड़ा ( उत्तर में ) से तमिलनाडु के अंत तक कन्याकुमारी ( दक्षिण में )

## पर्वत श्रृंखलाएँ

- नीलगिरी पर्वतमाला, शेवारॉय और तिरुमाला श्रृंखला
- सबसे ऊँची चोटी- अनामुडी ( केरल )

## नदियाँ ( उद्गम )

- पश्चिम की ओर बहने वाली: पेरियार, भरतपुड़ा, नेत्रवती, शरावती, मंडोवी
- पूर्व की ओर बहने वाली: गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगा, भद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमवती, काबिनी

## स्थानिक प्रजातियाँ

- नीलगिरी तहर ( IUCN स्थिति - EN )
- शेर पंछ मकाक ( IUCN स्थिति - EN )

## महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र

- बायोस्फीयर रिजर्व- अगस्त्यमाला और नीलगिरी
- राष्ट्रीय उद्यान- साइलेंट वैली, बांदीपुर, एराविकुलम, वायनाड-मुदुमलाई, नागरहोल
- बाघ अभयारण्य- कलक्कड़-मुंडनथुराई, पेरियार

## प्रमुख दर्रे

- थाल घाट दर्रा ( कसारा घाट )
- भोर घाट दर्रा
- पलक्कड़ दर्रा ( पाल घाट )
- अम्बा घाट दर्रा
- नानेघाट दर्रा
- अम्बोली घाट दर्रा

## महत्त्व

- जलविद्युत उत्पादन
- भारतीय मानसून मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है
- कार्बन पृथक्करण ( हर साल ~ 4 MT कार्बन को निष्प्रभावी बनाता )
- जैवविविधता के 8 वैश्विक सबसे महत्त्वपूर्ण हॉटस्पॉट में से एक ( प्रजातियों और स्थानिकता की समृद्धि के कारण )
- लोहा, मैंगनीज और बॉक्साइट अयस्कों, इमारती लकड़ी, काली मिर्च, इलायची, ऑयल पाम और रबर से समृद्ध
- सर्वाधिक आदिवासी आबादी ( PVTGs सहित )
- महत्त्वपूर्ण पर्यटन/तीर्थस्थल

## प्रमुख खतरे

- खनन, औद्योगीकरण
- वनोपज का बड़े पैमाने पर दोहन
- मानव-वन्यजीव संघर्ष, अतिक्रमण, अवैध शिकार
- पशुओं की चराई, वनों की कटाई
- बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ
- जलवायु परिवर्तन

## प्रमुखी समितियाँ

- गाडगिल समिति ( 2011 ) ( पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समिति )
  - सिफारिशें: श्रेणीबद्ध क्षेत्रों में सीमित विकास के साथ समूचे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ( ESA ) के रूप में घोषित किया जाना चाहिये।
- कस्तूरीरंगन समिति ( 2013 )
  - सिफारिश: समूचे क्षेत्र के बजाय, पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ESA के तहत लाया जाए + ESA में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

### ■ राज्यों की प्रतिक्रिया:

- इसमें शामिल सभी राज्यों द्वारा पश्चिमी घाटों की सुरक्षा की आवश्यकता को पहचाना गया लेकिन उन्होंने मसौदा अधिसूचना में उल्लिखित क्षेत्रों की अनुमत गतिविधियों एवं सीमाओं के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की।
- इन्होंने राज्य के विकास कार्यों को सुवधाजनक बनाने के क्रम में ESA को युक्तिसंगत बनाने का तरक दिया।
- कर्नाटक ने कस्तूरीरंगन पैनल की रिपोर्ट का वरिष्ठ कथित, जिसमें स्थानीय लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभावों को माध्यम बनाते हुए 20,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ESA के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था।
- गोवा ने ESA के रूप में प्रस्तावित 1,461 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कम करने का अनुरोध किया।

### नोट:

- ऐसे क्षेत्र जहाँ अनूठे जैविक संसाधन होते हैं और जनिके संरक्षण के लिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, MoEF&CC द्वारा पारस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESA) के रूप में अधिसूचित किये जाते हैं जिसका उद्देश्य पारस्थितिकी महत्त्व वाले क्षेत्रों में जैवविविधता की रक्षा करना है।
- इसके अतिरिक्त, जैवविविधता के प्रबंधन और संरक्षण के लिये, MoEF&CC संरक्षित क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zones- ESZ) भी नामित करता है।
  - वर्ष 2002 से, ये क्षेत्र वन्यजीवों के लिये अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिये बफर की भूमिका निभाई है, जो अत्यधिक संरक्षित क्षेत्रों को कम सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिये "शॉक एब्जॉर्बर" के रूप में कार्य करते हैं।

ESZ बनाम संरक्षित क्षेत्र		
वर्णना	संरक्षित क्षेत्र	पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)
प्राथमिक उद्देश्य	जैवविविधता और पारस्थितिकी तंत्र का पूर्ण संरक्षण	समीपवर्ती संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये बफर जोन के रूप में कार्य करता है
अवस्थिति	उच्च पारस्थितिकी मूल्य वाले निर्दिष्ट क्षेत्र	संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य) के समीप अवस्थिति
सुरक्षा का स्तर	उच्चतम स्तर की सुरक्षा	संरक्षित क्षेत्र पर प्रभाव को कम करने के लिये वनियमित गतिविधियाँ
विकासात्मक गतिविधियाँ	अत्यधिक प्रतिबंधित (केवल अनुसंधान, सीमित मनोरंजन उद्देश्यों हेतु)	विविध प्रकार- कुछ निषिद्ध, कुछ वनियमित, कुछ संवर्द्धित (सतत प्रथाएँ)
आजीविका	स्थानीय समुदाय का आगमन अमूमन प्रतिबंधित	परंपरागत प्रथाओं और सतत आजीविका के लिये उपयुक्त
आकार	परिवर्तनशील, दायरे में विस्तार संभव	प्रायः 10 कमी. के दायरे में सीमित, संरक्षित क्षेत्रों की तुलना में छोटे

### पश्चिमी घाट पर समितियों की सफारिशें:

- पश्चिमी घाट पारस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, 2011 (अध्यक्ष: माधव गाडगलि):
  - पश्चिमी घाट के सभी क्षेत्रों को ESA घोषित किया जाए तथा श्रेणीबद्ध क्षेत्रों में सीमित विकास की अनुमति दी जाए।
  - पश्चिमी घाटों को ESA 1, 2 तथा 3 में वर्गीकृत किया जाए, जिसमें ESA- 1 को उच्च प्राथमिकता दी जाए, जहाँ लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियाँ प्रतिबंधित हों।
  - शासन की प्रणाली को अधरोर्ध्व (Top-To-Bottom) दृष्टिकोण के बजाय ऊर्ध्वाधर (Bottom-To-Top) दृष्टिकोण (ग्राम सभाओं से) के रूप में निर्दिष्ट किया जाए।
  - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत शक्तियों के साथ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में पश्चिमी घाट पारस्थितिकी प्राधिकरण (WGEA) का गठन किया जाए।
  - रिपोर्ट की आलोचना इस आधार पर की गई यह यथार्थ से परे है और पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूल है।
- कस्तूरीरंगन समिति, 2013: इसमें गाडगलि रिपोर्ट के विपरीत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया:
  - पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के बजाय, कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ESA के अंतर्गत लाया जाएगा।
  - ESA में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध।
  - किसी भी ताप वदियुत परियोजना की अनुमति नहीं दी जाएगी और वसित्त अध्ययन के बाद ही जल वदियुत परियोजनाओं की अनुमति दी जाएगी।
  - लाल उद्योग यानी जो अत्यधिक प्रदूषण करते हैं, उन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा।
  - ESA के दायरे से बसे हुए क्षेत्रों और बागानों को बाहर रखा जाएगा, जिससे यह किसानों के पक्ष में होगा।

### पारस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- **संरक्षण और विकास में संतुलन:** ESA अक्सर **आर्थिक विकास की संभावना** वाले क्षेत्रों में स्थिति होते हैं। इससे संरक्षण लक्ष्यों और विकास परियोजनाओं के बीच टकराव हो सकता है, **जसिसे स्थानीय समुदायों को आर्थिक अवसरों से वंचित होना** पड़ सकता है।
- **स्थानीय आजीविका पर प्रभाव:** ESA में वनियमन वहाँ रहने वाले समुदायों की **पारंपरिक प्रथाओं** और आजीविका को प्रतर्बिधति कर सकते हैं। इससे नाराज़गी पैदा हो सकती है तथा संरक्षण पर्याप्तों में सहयोग में बाधा आ सकती है।
- **असंगत नीतियाँ एवं कार्यान्वयन:** ESA की नीतियाँ और कार्यान्वयन अलग-अलग क्षेत्रों व राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं, जसिसे प्रवर्तन में भ्रम तथा चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। यह असंगतता उन गतिविधियों के लिये खामियाँ भी पैदा कर सकती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकती हैं।
- **जागरूकता और भागीदारी का अभाव:** कभी-कभी, स्थानीय समुदाय और हतिधारक ESA के महत्त्व के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं हो सकते हैं या नरिणय लेने की प्रक्रिया में उचित रूप से शामिल नहीं हो सकते हैं। भागीदारी की यह कमी प्रतरीध को जन्म दे सकती है और कार्यक्रम की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकती है।

## आगे की राह

- **संतुलति दृष्टिकोण:** संतुलति दृष्टिकोण के लिये प्रयास करें, जो सतत् विकास की अनुमति देते हुए **पश्चिमी घाट** की पारस्थितिकि अखंडता की रक्षा करता है। इसमें मुख्य क्षेत्रों में सख्त नियमों के साथ ESA में शामिल होना और वशिष्ट कम प्रभाव वाली विकास परियोजनाओं के लिये नरिदष्टि क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।
- **वैज्ञानिकि प्रभाव मूल्यांकन:** ESA पदनाम के लिये आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र नरिधारति करने हेतु **संपूरण, स्वतंत्र वैज्ञानिकि मूल्यांकन** करना। यह साक्ष्य-आधारति नरिणय लेने को सुनश्चिति करता है और विकास पर अनावश्यक प्रतर्बिधों को भी कम करता है।
- **हतिधारकों की वचनबद्धता:** केंद्रीय सरकारी नकियों, राज्य सरकारों, स्थानीय समुदायों के साथ-साथ पर्यावरण समूहों के **बीचखुले संचार एवं सहयोग को सुवधिजनक बनाना**। इससे नरिणय लेने की प्रक्रिया अधिक समावेशी हो जाती है, जसिमें सभी हतिधारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।
- **वैकल्पिकि आजीविका विकल्प:** ESA में रहने वाले उन लोगों के लिये वैकल्पिकि **आजीविका विकल्प विकसित करना** जो कठोर नियमों से प्रभावति हो सकते हैं। इसमें इको-टूरिज़्म धारणीय कृषि पद्धतियों के साथ-साथ कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना भी शामिल हो सकता है।
- **पारदर्शी मॉनटरिंग:** ESA एवं विकास परियोजनाओं की **प्रभावशीलता पर नज़र रखने के लिये स्पष्ट तथा पारदर्शी नगिरानी तंत्र** स्थापति करना। इससे अनपेक्षति परिणाम सामने आने पर सुधार की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा और ज़मिमेदारीपूरण विकास प्रथाओं को सुनश्चिति किया जा सकेगा।

### दृष्टिभेन्स प्रश्न:

**प्रश्न.** भारत के पश्चिमी घाटों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों से नपिटने हेतु एक संतुलति दृष्टिकोण क्या हो सकता है?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

**प्रश्न.** भारत में संरक्षति क्षेत्रों की नमिनलखिति में से कसि एक श्रेणी में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? (2012)

- बायोस्फीयर रज़िर्व
- राष्ट्रीय उद्यान
- रामसर कन्वेंशन के तहत घोषति आर्रभूमि
- वन्यजीव अभयारण्य

**उत्तर: (b)**

**??????????:**

**प्रश्न.** "वभिन्नि प्रतयोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतगित वशिधाभासों के परिणामस्वरूप पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके नमिनीकरण की रोकथाम अपर्याप्त रही है"। सुसंगत उदाहरणों सहति टपिपणी कीजिये। (2018)